कानपुर, शुक्रवार, 17 अप्रैल, २०२६
वर्षः 03, अंकः 96, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड बजरंग लाल तापड़िया फोर्ब्स सूची में शामिल..>Pg12
2 अस्पताल सीज, 6 को नोटिस, 8 के ओटी पर ताला...>Pg03
मूल्यः 2 ₹

उन्नाव दुष्कर्म केस में मौत की सजा की मांग पर हाई कोर्ट का तीखा सवाल

5 साल बाद क्यों याद आई फांसी...

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली/उन्नाव। बहुचर्चित उन्नाव दुष्कर्म कांड से जुड़े एक अहम कानूनी घटनाक्रम में दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता की ओर से दाखिल उस अपील पर सख्त रुख अपनाया है, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की मौत के मामले में मौत की सजा देने की मांग की गई है। अदालत ने करीब 1940 दिनों (लगभग 5 साल से अधिक) की देरी पर गंभीर सवाल उठाते हुए पीड़िता से विस्तृत जवाब तलब किया है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि अपील दाखिल करने की समय-सीमा तय होती है और इतने लंबे विलंब को केवल ठोस और विश्वसनीय कारणों के आधार पर ही माफ किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पीड़िता अन्य संबंधित मामलों में लगातार सक्रिय रही हैं, ऐसे में यह समझना जरूरी है कि इसी मामले में अपील दाखिल करने में इतना लंबा समय क्यों लग गया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में समयसीमा का पालन बेहद महत्वपूर्ण है। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा ने दलील दी कि पीड़िता बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रही थीं और बावजूद इसके उन्होंने अन्य मामलों को आगे बढ़ाया। उन्होंने सवाल उठाया "क्या तकनीकी देरी सच्चाई और न्याय पर भारी पड़ सकती है?"

सेंगर पक्ष का विरोधः "मीडिया ट्रायल की कोशिश": वहीं, आरोपी पक्ष की ओर से अपील का विरोध करते हुए कहा गया कि इतनी लंबी देरी के बाद अपील दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे "मीडिया ट्रायल" बनाने की कोशिश की जा रही है।

⇨ **उन्नाव दुष्कर्म कांड में नया मोड़ 1940 दिन की देरी पर हाईकोर्ट सख्त, पीड़िता से मांगा जवाब**

क्या है मामला?

यह मामला वर्ष 2018 के चर्चित उन्नाव दुष्कर्म कांड से जुड़ा है, जिसमें आरोप था कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के प्रभाव में पुलिस ने पीड़िता के पिता को झूठे मामले में गिरफ्तार किया और हिरासत में उनके साथ मारपीट की गई, जिससे 9 अप्रैल 2018 को उनकी मौत हो गई। इस मामले में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने 13 मार्च 2020 को सेंगर और उसके भाई जयदीप सेंगर को 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

क्या तकनीकी देरी न्याय को प्रभावित करती है?

भारतीय न्याय व्यवस्था में अपील दाखिल करने की समय-सीमा का सख्ती से पालन होता है। हालांकि, अदालतें "पर्याप्त कारण" होने पर देरी को माफ कर सकती हैं। इस मामले में सवाल यह है कि क्या पीड़िता की परिस्थितियां इतनी असाधारण थीं कि 5 साल की देरी को न्यायोचित ठहराया जा सके।

सजा बढ़ाने की मांग कितनी मजबूत है कानूनी स्थिति?

ट्रायल कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा पहले ही दी जा चुकी है। ऐसे में मौत की सजा की मांग के लिए यह साबित करना होगा कि अपराध "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" श्रेणी में आता है। देरी के कारण अपील की स्वीकार्यता भी चुनौती बन सकती है।

हाई-प्रोफाइल मामलों में न्याय बनाम प्रक्रिया

उन्नाव कांड जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में न्याय और प्रक्रिया के बीच संतुलन अहम हो जाता है। अदालतें एक ओर पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करती हैं, वहीं दूसरी ओर कानूनी प्रक्रिया की पवित्रता भी बनाए रखना जरूरी होता है।

उन्नाव कांड से अब तक

- **जून 2017** - उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप
- **अप्रैल 2018** - पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद मौत
- **अप्रैल 2018** - मामला तूल पकड़ने पर सेंगर की गिरफ्तारी
- **2019** - सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर
- **दिसंबर 2019** - दुष्कर्म मामले में सेंगर को उम्रकैद
- **मार्च 2020** - पिता की मौत के मामले में 10 साल की सजा
- **2025-26** - पीड़िता की ओर से मौत की सजा की मांग करते हुए अपील
- **2026** - दिल्ली हाईकोर्ट ने 1940 दिन की देरी पर जवाब मांगा

- 1940 दिन की देरी पर हाईकोर्ट सख्त
- पीड़िता से मांगा गया विस्तृत स्पष्टीकरण
- ट्रायल कोर्ट पहले ही दे चुका है 10 साल की सजा
- पीड़िता की मांग, सजा बढ़ाकर फांसी की जाए
- अदालत का फोकस "क्या देरी न्याय को प्रभावित करती है?"

2027 से पहले योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल तय!

दिल्ली दरबार में यूपी का 'पावर प्लान'

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों तेज उबाल पर है। योगी आदित्यनाथ सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बड़े बदलावों को लेकर सियासी हलचल अब अपने निर्णायक दौर में पहुंचती दिख रही है। लखनऊ में मैराथन बैठकों के बाद अब पूरा फोकस दिल्ली पर शिफ्ट हो गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अंतिम रणनीति तय करने में जुटा है।

गुरुवार को प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच देर रात तक चली बैठकों में सरकार के प्रदर्शन, जनसंतुष्टि और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर गहन मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक, यह महज औपचारिक समीक्षा नहीं, बल्कि एक बड़े 'पॉलिटिकल रीसेट' की तैयारी है, जिसमें सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर बदलाव संभव हैं।

बताया जा रहा है कि पार्टी ने हाल के फीडबैक, क्षेत्रीय रिपोर्ट और जातीय समीकरणों के विश्लेषण के आधार पर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। खासकर उन क्षेत्रों पर ध्यान है, जहां पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से पकड़ मजबूत करनी है।

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है कि कई खाली पदों पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल भी तय माना जा रहा है। यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने वाला होगा यानी 'परफॉर्म या पेरिश' की लाइन पर सरकार आगे बढ़ सकती है।

सबसे अहम फोकस सामाजिक संतुलन पर है। पार्टी कुर्मी, पासी, शाक्य, मौर्य जैसे ओबीसी और दलित वर्गों के साथ-साथ सवर्ण वोट बैंक को भी साधने की रणनीति पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि इसी आधार पर मंत्रिमंडल की नई तस्वीर तैयार होगी, ताकि 2027 के चुनाव में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

सिर्फ सरकार ही नहीं, संगठन में भी बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। प्रदेश इकाई में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति, जिला स्तर पर फेरबदल और आयोगों-निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए कार्यकर्ताओं को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। इससे पार्टी कैडर में नई ऊर्जा भरने की कोशिश होगी। दिल्ली में चल रहे मंथन को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह फैसला सीधे तौर पर 2027 की चुनावी जमीन तैयार करेगा। पार्टी नेतृत्व कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रहा और हर कदम बेहद सोच-समझकर उठाने की तैयारी है।

⇨ **सामाजिक समीकरण साधने की कवायद तेज, नए चेहरों की एंट्री और संगठन में बड़े बदलाव के संकेत**

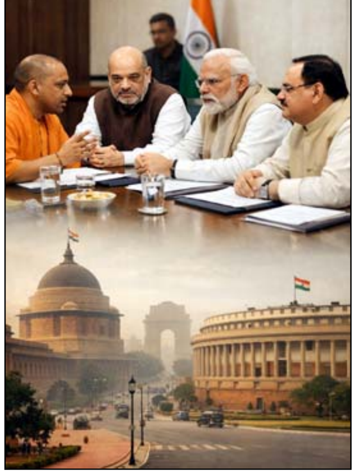

परफॉर्मेंस बनाम पॉलिटिक्स

मंत्रिमंडल विस्तार में परफॉर्मेंस एक बड़ा फैक्टर रहेगा। जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड कमजोर है, उनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। इसके साथ ही नए चेहरों को मौका देकर 'एंटी-इंकम्बेंसी' को भी कम करने की रणनीति है।

'सोशल इंजीनियरिंग' का मास्टर स्ट्रोक

भाजपा की रणनीति साफ है–सिर्फ विकास के मुद्दे नहीं, बल्कि जातीय और सामाजिक समीकरणों को भी बराबर तवज्जो। कुर्मी, मौर्य, शाक्य जैसे प्रभावशाली ओबीसी वर्गों और पासी जैसे दलित समुदायों को साधना 2027 की जीत की कुंजी माना जा रहा है।

संगठन से सरकार तक एक ही लाइन

भाजपा इस बार सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दे रही है। संगठन में बदलाव, आयोग-निगमों में नियुक्तियां और कैबिनेट विस्तार ये तीनों कदम एक ही बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका लक्ष्य 2027 में सत्ता की वापसी सुनिश्चित करना है।

स्कूल या शॉपिंग मॉल?

शिक्षा के नाम पर खुली लूट कानपुर में अभिभावक बेहाल

नए सत्र में किताब-कॉपी से लेकर स्टेशनरी तक 'कमीशन गेम', तय दुकानों से खरीदारी का दबाव

» स्वराज इंडिया ब्यूरो।

खास खबर

कानपुर। शहर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। शिक्षा का मंदिर अब 'कमाई का केंद्र' बनता नजर आ रहा है, जहां बच्चों की पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों की जेब पर खुला डाका डाला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कूल अब शिक्षा देने के बजाय 'शॉपिंग मॉल' बन चुके हैं? क्योंकि अभिभावकों को किताब-कॉपी और स्टेशनरी खरीदने के लिए खुलेआम तय दुकानों पर भेजा जा रहा है और कहीं-कहीं तो स्कूल परिसर में ही अस्थायी दुकानें सजा दी गई हैं।

तय दुकानों से खरीदारी का दबाव

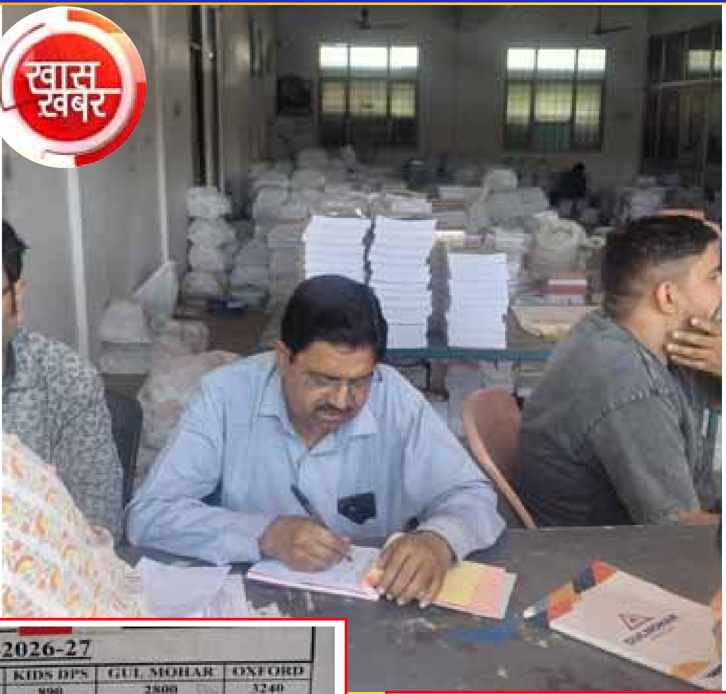

RATE LIST-2026-27

CLASS	ALLBRIGHT	CLASS	KDMA	KIDS DPS	GUL MOHAR	OXFORD
PG	3865	PG	4460	890	2800	3240
LKG	4560	LKG	5195	1390	3315	3515
UKG	4665	UKG	4740	1145	4200	3645
I	6065	I	5755	3080	5675	5030
II	6335	II	5920	3290	6105	5145
III	7095	III	7250	6275	7220	5740
IV	7075	IV	7435	6565	7770	6110
V	7655	V	7990	6855	8450	6575
VI	9475	VI	8870	8175	8855	6545
VII	9665	VII	8555	8365	9175	6625
VIII	9850	VIII	8915	8775	8920	6835
IX-PHY	10220	X-CMP	7910		7485	
IX-COMP.	10255	IX-ART	7360			
IX-COMM.	7910	X-COMP	8375		9375	
X-PHY.	[illegible]	X-ART	7810			
X-COMP	7890					
X-COMM	8220					

अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल केवल बुक लिस्ट ही नहीं देते, बल्कि सीधे दुकान का नाम और पता भी थमा देते हैं। साफ चेतावनी दी जाती है कि बाहर से सामान खरीदने पर सिलेबस अलग हो सकता है, जिससे बच्चे को नुकसान होगा। ऐसे में अभिभावक मजबूरी में महंगा सामान खरीदने को विवश हैं।

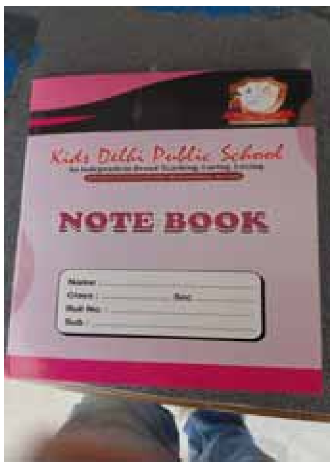

बाजार से 2 से 4 गुना महंगा सामान

जांच में सामने आया है कि वही किताबें और कॉपियां, जो बाजार में सामान्य कीमत पर मिलती हैं, स्कूल द्वारा तय दुकानों पर दोगुने-चौगुने दामों पर बेची जा रही हैं।

» 120 पेज कॉपी-25 से बढ़ाकर 60

» 200 पेज कॉपी-45 से बढ़ाकर 90

फेवीकोल-30 से 70

» क्रेयॉन/कलर- 80 से 140

यह अंतर साफ बताता है कि इस पूरे खेल में मोटा कमीशन शामिल है।

» नर्सरी से 8वीं तक 'भारी बोझ'

» शिक्षा का खर्च अब अभिभावकों के लिए किसी आर्थिक संकट से कम नहीं है।

» नर्सरी बुकसेट- 3000-4000

कक्षा 8 तक बुकसेट-8000 से अधिक

» कम आय वाले परिवारों के लिए यह खर्च उठाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है।

स्कूल परिसर में ही 'दुकानदारी'

कई स्कूलों ने अपने परिसर के अंदर ही बुक स्टॉल लगाकर अभिभावकों के विकल्प खत्म कर दिए हैं। अभिभावकों का कहना है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित व्यवस्था है, जिससे बाहर से खरीदारी की गुंजाइश ही खत्म कर दी जाती है।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

सब कुछ खुलेआम होने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर किसके संरक्षण में यह 'शिक्षा माफिया' फल-फूल रहा है?

अभिभावकों का दर्द

अभिभावकों का कहना है कि वे बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में महंगा सामान खरीदना पड़ता है। लेकिन यह स्थिति अब असहनीय होती जा रही है।

बिना कोचिंग अंशुमान ने रचा इतिहास सीबीएसई में 97प्रतिशत अंक

» संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

कानपुर। कानपुर के कैंब्रिज पब्लिक स्कूल, रतनपुर के छात्र अंशुमान पटेल ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 97प्रतिशत अंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है। खास बात यह रही कि अंशुमान ने बिना किसी कोचिंग के केवल सेल्फ-स्टडी के दम पर यह मुकाम हासिल किया ।उनके पिता जयकुमार पटेल पुलिस विभाग में तैनात हैं, जिनके अनुशासन और माता नेहा पटेल के सहयोग ने उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई। अंशुमान ने नियमित पढ़ाई, एकाग्रता और दृढ़ निश्चय को अपनी सफलता का मूल मंत्र बताया ।अंशुमान आगे चलकर देश सेवा करना चाहते हैं। उनकी उपलब्धि से परिवार, स्कूल और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

कल्याणपुर में 'फर्जी इलाज' के काले कारोबार पर स्वास्थ्य विभाग का चला हंटर

2 अस्पताल सीज, 6 को नोटिस 8 के ऑपरेशन थियेटर पर ताला

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कल्याणपुर में अवैध अस्पतालों के खिलाफ आखिरकार स्वास्थ्य विभाग का डंडा पूरी ताकत से चला और 'इलाज' के नाम पर चल रहे काले खेल की परतें खुलकर सामने आ गईं। शुक्रवार को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी रमित रस्तोगी की अगुवाई में चली कार्रवाई ने इलाके के कई अस्पताल संचालकों की पोल खोल दी। दो अस्पतालों को मौके पर ही सील कर दिया गया, जबकि छह को नोटिस थमा दिया गया। इतना ही नहीं, आठ अस्पतालों की ऑपरेशन थिएटर (ओटी) सीज कर दी गईं यानी मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का पूरा इंतजाम ठप कर दिया गया।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखते ही कई अस्पताल संचालक ताला डालकर मौके से फरार हो गए। यह साफ इशारा है कि इन अस्पतालों में सब कुछ 'नियमों के खिलाफ' चल रहा था। छापेमारी के दौरान स्टार श्री हॉस्पिटल और कानपुर हेल्थ हॉस्पिटल पूरी तरह बिना पंजीकरण के चलते पाए गए। इन दोनों अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया और तीन दिन के भीतर परिसर खाली

⇨ **बिना पंजीकरण धड़ल्ले से चल रहे अस्पताल, टीम पहुंचते ही संचालक फरार, अब थाने से होगी सख्त कार्रवाई**

- 2 अस्पताल पूरी तरह सीज, 6 को नोटिस
- 8 अस्पतालों की ओटी पर ताला
- कई संचालक टीम को देखते ही फरार
- बिना रजिस्ट्रेशन अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क उजागर
- पुलिस स्तर पर भी अब होगी कार्रवाई

करने का अल्टीमेटम दिया गया।

वहीं, बारासिरोही स्थित गांधी हॉस्पिटल, मान्या हॉस्पिटल और संवारिया हॉस्पिटल के संचालक टीम को देखते ही ताला लगाकर फरार हो गए। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ अब पुलिस स्तर से कार्रवाई की तैयारी है, जिससे साफ है कि मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि कानूनी शिकंजे तक पहुंच चुका है। निरीक्षण के दौरान कई अस्पतालों में बुनियादी मानकों की भी धज्जियां उड़ती मिलीं। रोहित राज हॉस्पिटल की ओटी मानक पूरे न होने पर सीज कर दी गई, जबकि एचआर हॉस्पिटल और न्यू अभिनव हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के चलते पाए गए, जिन पर भी कार्रवाई की गई। हालांकि, कुछ अस्पतालों में स्थिति संतोषजनक भी मिली। ओसियम हॉस्पिटल, माँ सरस्वती हॉस्पिटल और साक्षी हॉस्पिटल में डॉक्टर और सफाई व्यवस्था ठीक पाई गई, जिन्हें केवल सुधार के निर्देश देकर छोड़ा गया। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी रमित रस्तोगी ने साफ कहा कि अब तक करीब 15 अस्पताल सीज किए जा चुके हैं और 20 से ज्यादा को नोटिस दिया गया है। बिना पंजीकरण अस्पताल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

'जिंदगी से खिलवाड़' का धंधा

कल्याणपुर में जिस तरह बिना पंजीकरण अस्पताल चल रहे थे, वह सीधे तौर पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। बिना प्रशिक्षित स्टाफ और अधूरी सुविधाओं के साथ ऑपरेशन करना एक तरह का 'मौत का खेल' साबित हो सकता था।

सिस्टम की लापरवाही या मिलीभगत?

इतने बड़े पैमाने पर अवैध अस्पतालों का चलना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र फेल हो चुका है या कहीं न कहीं मिलीभगत भी है। अगर पहले ही सख्ती होती, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती।

अब आगे क्या होगा ?

अब असली परीक्षा यह है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ 'दिखावा' बनकर रह जाएगी या लगातार अभियान चलाकर पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाएगा। अगर सख्ती जारी रही तो ही मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

आईआईटी कानपुर के केंद्रीय विद्यालय में जल पखवाड़ा शुरू

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। केंद्रीय विद्यालय, आईआईटी कानपुर में गुरुवार से जल पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका प्रियंका तिवारी ने समस्त विद्यालय परिवार को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने विद्यार्थियों को जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए प्रेरित करते हुए पानी के महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए जल संरक्षण के विभिन्न उपाय बताए और सभी को जल बचाने के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य रवीश चंद्र पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि जल संरक्षण केवल शपथ तक सीमित न रहे, बल्कि इसे दैनिक जीवन में अपनाना जरूरी है। उन्होंने सभी से जल के विवेकपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।

⇨ **विद्यार्थियों ने लिया संरक्षण का संकल्प**

⇨ **30 अप्रैल तक चलेंगी जागरूकता गतिविधियां, जल बचाने का संदेश हुआ प्रखर**

इस अवसर पर रूपम मिश्रा ने विद्यार्थियों से जल संरक्षण विषय पर नारे लिखवाए, ताकि समाज में भी इस दिशा में जागरूकता बढ़ सके। विद्यालय प्रशासन के अनुसार, जल पखवाड़ा 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसके दौरान विभिन्न शैक्षिक व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

ड्यूटी से गायब 12 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, सभी सस्पेंड

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। अनुशासनहीनता और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से बिना किसी सूचना और अनुमति के गैरहाजिर चल रहे 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार ये सभी पुलिसकर्मी काफी समय से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थे और बार-बार सूचना देने के बावजूद भी इन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

⇨ **लंबे समय से बिना सूचना गैरहाजिर रहने और आदेश के बावजूद ड्यूटी जॉइन न करने पर कार्रवाई**

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि संबंधित पुलिसकर्मियों को कई बार नोटिस जारी कर ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए विभाग ने सख्त कदम उठाया और सभी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।

अधिकारियों का कहना है कि पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि ड्यूटी के प्रति उदासीनता दिखाने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी, ताकि पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही और कार्यकुशलता बनी रहे।

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

यह पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड

- दरोगा मोनू सिंह (54 दिन से गायब)
- दरोगा राजेन्द्र कुमार तिवारी (139 दिन से गायब
- कांस्टेबल दुष्यंत (168 दिन से गायब)
- कांस्टेबल अंकुर (135 दिन से गायब)
- कांस्टेबल करन (49 दिन से गायब)
- कांस्टेबल जितेन्द्र (43 दिन से गायब)
- कांस्टेबल प्रवीन कुमार (40 दिन से गायब)
- कांस्टेबल प्रवीन कुमार (40 दिन से गायब)
- कांस्टेबल भूपेन्द्र (52 दिन से गायब)
- कांस्टेबल रवि (107 दिन से गायब

केडीए की उन्नाव में बड़ी कार्रवाई

अवैध निर्माणों पर सील, 6800 वर्ग मीटर क्षेत्र सीलिंग, 18000 वर्ग मीटर में नोटिस

» शुक्लागंज-उन्नाव में प्लॉटिंग और गेस्ट हाउस पर शिकंजा, 15 दिन में स्वयं ध्वस्तीकरण के निर्देश

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर/उन्नाव। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने गुरुवार को शुक्लागंज-उन्नाव क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर सीलिंग और नोटिस जारी किए। इस अभियान के तहत कुल 6800 वर्ग मीटर क्षेत्र में सीलिंग की गई, जबकि लगभग 18000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए।

केडीए की टीम ने ग्राम देवारा खुर्द, सहजनी (उन्नाव) में देशराज चौहान व अन्य द्वारा लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर सीलिंग की कार्रवाई की। वहीं, तारा रानी कान्वेंट स्कूल के पास गौरी शुक्ला व अन्य द्वारा करीब 800 वर्ग मीटर क्षेत्र में संचालित गेस्ट हाउस को भी सील कर दिया गया।

इसके अलावा ग्राम पिंडोखा, देवारा कला में भूरेलाल द्वारा पूर्व में सील किए गए परिसर की सील हटाकर दोबारा निर्माण करने का मामला सामने आने पर प्राधिकरण ने सख्ती दिखाते हुए परिसर को पुनः सील कर दिया।केडीए ने सिंहपुर कछार क्षेत्र में अभिषेक कटियार, सुशील कटियार व अन्य द्वारा लगभग 10000 वर्ग मीटर में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया है। संबंधित विकासकर्ताओं को 15 दिन के भीतर स्वयं निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इसी क्रम में देवारा खुर्द में राजाराम, रंजीत लाल, बुद्धिलाल व अन्य द्वारा 3000 वर्ग मीटर, रंजीत पाल व अन्य द्वारा 2000 वर्ग मीटर तथा पिंडोखा क्षेत्र में राहुल सलोनिया व अन्य द्वारा लगभग 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ भी नोटिस जारी किए गए हैं।केडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग अवैध है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नगर निगम में मारपीट पर सख्त कार्रवाई, दो कर्मचारी तत्काल हुए निलंबित

सोशल मीडिया वीडियो से खुलासा, पैसों के विवाद में गाली-गलौज और हाथापाई

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

नगर निगम मुख्यालय स्थित नागरिक सुविधा केंद्र (जोन-2) में अनुशासनहीनता का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।जानकारी के अनुसार, कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज के साथ हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना से न केवल नगर निगम की छवि धूमिल हुई, बल्कि कार्यालयीन कार्य भी बाधित हुआ।प्रकरण की जांच में प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता के आरोप सही पाए जाने पर नगर निगम प्रशासन ने सूरज कुमार (कनिष्ठ लिपिक, परियोजना विभाग) और नरेंद्र कुमार (चपरासी, जोन-2) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच सौंपी गई है।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, कदाचार या कार्यालयीन मर्यादा के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने आचरण में अनुशासन बनाए रखें और निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करें।

हैलेट से फरार हुआ मुठभेड़ का आरोपी, पुलिस सुरक्षा पर उठे सवाल

» तीन पहिया ऑटो से भागा लुटेरा, शहरभर में सघन चेकिंग अभियान शुरू

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर साउथ जोन के बर्रा थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई लूट की वारदात में शामिल शातिर आरोपी मुन्ना खान के पुलिस अभिरक्षा से फरार होने की घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए आरोपी को उपचार के लिए हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।जानकारी के अनुसार, बर्रा क्षेत्र में हुई लूट की घटना के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी मुन्ना खान को मुठभेड़ में दबोच लिया था। मुठभेड़ में घायल होने के कारण उसे तत्काल हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इलाज के दौरान ही आरोपी पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।सूत्रों के मुताबिक, फरार आरोपी अस्पताल परिसर से तीन पहिया ऑटो के जरिए मौके से निकल गया।। विभिन्न थानों की पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है।

दस सूत्रीय मांगों पर आयकर कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, 13 मई तक आंदोलन की चेतावनी

मध्यावकाश में विरोध, धरना-वॉकआउट और हड़ताल की रूपरेखा तय

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। आयकर कर्मचारी महासंघ एवं आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सर्किल की संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर गुरुवार को कानपुर मुख्यालय स्थित आयकर भवन, सिविल लाइंस में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मध्यावकाश के दौरान जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केंद्रीय संयुक्त संघर्ष समिति, नई दिल्ली के निर्देश पर दस सूत्रीय मांगों के समर्थन में आयोजित किया गया।

प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित संकल्प पत्र प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अर्पना करन को अग्रसारित करने हेतु सौंपा गया। संयुक्त संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन 16 अप्रैल से शुरू होकर 13 मई तक चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा, जिसमें मध्यावकाश प्रदर्शन, धरना, वॉकआउट और आवश्यक होने पर हड़ताल भी शामिल है।सभा को संबोधित करते हुए आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ के महासचिव राघवेन्द्र सिंह और आयकर कर्मचारी महासंघ के महासचिव सुनील कुमार ने कहा कि लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान न होने के कारण कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है। उन्होंने सरकार से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत मांगों में कैडर रिव्यू एवं पुनर्गठन प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप देने, वर्ष 2014 बैच एवं उसके बाद के अधिकारियों की समस्याओं का समाधान, आयकर अधिकारियों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देना, भर्ती नियमों में संशोधन, इंटर चार्ज ट्रांसफर नीति की पुनर्बहाली, वेतन विसंगतियों का निस्तारण, लैपटॉप उपलब्ध कराने तथा अव्यावहारिक रिपोर्टिंग प्रणाली समाप्त करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।

अध्यक्षता व संचालन

प्रदर्शन की अध्यक्षता एस.के. वर्मा (अध्यक्ष, ढूझ्ब्रह) एवं बृजेश कुमार (सर्किल अध्यक्ष, ढूझ्श्रख्र) ने की, जबकि संचालन संयोजक शरद प्रकाश अग्रवाल ने किया।

कार्यक्रम में शांति भूषण मिश्रा, शिवेन्दु श्रीवास्तव, नवनीत शुक्ला, पंकज यादव, मुकेश कुमार, अनिल चौधरी, शिव कुमार, वैभव सचान, रजत सिंह, रवि कुमार, शिवम पाल, के.के. शुक्ला, राजेश तिवारी, मोहन लाल मुकेश, संजय कुमार, प्रवीण बाजपेयी, अनुराग बाजपेई, गीता टण्डन कपूर, अनूप तिवारी, विवेक दीक्षित, राम प्रताप, तन्मय त्रिपाठी, दीपंकर चौरसिया, क्षितिज शुक्ला, राजेश गौर, उमेश वर्मा, अजय वर्मा, ब्रजेश पांडेय, उमाशंकर मौर्या, शशांक ज्योति सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

चेतावनी

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

सम्पादकीय

नासिक यौन उत्पीड़न मामले से सुरक्षा खामियां उजागर

देश की एक प्रमुख आईटी कंपनी की नासिक शाखा में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयासों के चौंकाने वाले आरोप परेशान करने वाले हैं। निस्संदेह, यह प्रकरण बेहद गंभीर है और इन आरोपों ने कार्यस्थल की सुरक्षा जैसे नजरअंदाज किए जा रहे महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर देश का ध्यान आकर्षित किया है। यह आरोप है कि पुरुष कर्मचारियों का एक समूह महिला सहकर्मियों को निशाना बनाने के लिए एक 'संगठित गिरोह' की तरह काम कर रहा था। निश्चित रूप से यह घटनाक्रम कंपनी प्रबंधन की उस घोर लापरवाही को ही उजागर करता है जिस के चलते समय रहते इस तरह के यौन उत्पीड़न व धर्म परिवर्तन की कोशिशों पर अंकुश नहीं लग सका। यह विडंबना ही है कि मानव संसाधन प्रबंधक ने कथित तौर पर पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से यह कहकर रोका कि 'ऐसी चीजें होती रहती हैं।' आक्षेप लगाया गया है कि इस प्रकरण में आरोपी का ही पक्ष लिया गया। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम कॉर्पोरेट जगत में व्याप्त विद्रूपताओं और एक गहरी तथा व्यापक विफलता की ओर ही इशारा करता है। जबकि दावा यह किया जाता रहा है कि कॉर्पोरेट जगत की प्राथमिकता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चत करना है। इसमें दो राय नहीं है कि जब यौन उत्पीड़न रोकथाम ढांचे को लागू करने के लिये जिम्मेदार उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों पर दुर्व्यवहार को सामान्य या मामूली बात समझने का आरोप लगता है, तो सारे संस्थागत सुरक्षा उपाय ध्वस्त हो जाते हैं। निर्विवाद रूप से यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है, जब पीड़ित महिला कर्मचारी को न केवल अपराधियों द्वारा बल्कि उनकी सुरक्षा का दायित्व संभालने वालों द्वारा भी चुप कराने के प्रयास किये जाते हैं। जिसके बाद ही मामले में प्राथमिकी दर्ज हो पायी है।

बहरहाल, इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को लेकर एक असहज करने वाला प्रश्न यह उठता है कि क्यों भय, सामाजिक कलंक अथवा संस्थागत उदासीनता के कारण देश भर के विभिन्न कार्यस्थलों में ऐसे कितने ही यौन उत्पीड़न के मामले उजागर नहीं हो पाते हैं? इसमें दो राय नहीं कि इस मामले में जांच बिना किसी पूर्वाग्रह के आगे बढ़नी चाहिए। निर्विवाद रूप से आईटी कंपनी के नासिक प्रकरण में सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग देने का प्रयास इस संकट की मूल चिंताओं को धूमिल करने का जोखिम जरूर पैदा कर सकता है। निस्संदेह, ऐसी घटनाओं को धार्मिक या वैचारिक नजरिये से देखना कॉर्पोरेट जवाबदेही और लैंगिक संवेदनशीलता वाले सुधारों की तत्काल आवश्यकता से ध्यान भटका सकता है। इस संवेदनशील विषय पर नजर रखने वाले तर्क देते हैं कि उत्पीड़न को संप्रदाय विशेष के अपराध के रूप में देखने के बजाय, इसे एक अधिकारी द्वारा अपने अधिकार के दुरुपयोग के रूप में देखा जाना चाहिए, जो किसी भी संस्थान में पारदर्शिता और प्रवर्तन की कमी वाले वातावरण में ही पनपता है।

इस विचलित करने वाले प्रकरण में अधिकारियों की प्रतिक्रिया, जिसमें एक विशेष जांच दल का गठन भी शामिल है, स्वागत योग्य है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में महिला आयोग द्वारा भी एक स्वतंत्र जांच की जा रही है, जो कि एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। हालांकि, कॉर्पोरेट जगत से जुड़े कार्यालयों में स्थायी परिवर्तन तभी संभव होगा जब कंपनियां ऐसे मामलों में 'शून्य सहिष्णुता' की घोषणा करेंगी। इसके साथ ही जरूरत इस बात की भी कि कार्यालयों में ऐसा निर्भयतापूर्ण वातावरण तैयार किया जाए कि कोई भी महिला कर्मचारी बिना डर के बोलने के लिये सशक्त बन सके। उन्हें सशक्त बनाने के लिये आंतरिक तंत्र को सक्रिय रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है।

अतीत की गाथाएं भविष्य की दिशा

डा0 सुधीर कुमार सचदेवा

विश्व धरोहर स्थलों का महत्व केवल ऐतिहासिक स्मारकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवता की सांस्कृतिक धरोहर और विकास की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त ये स्थल न केवल अतीत की याद दिलाते हैं, बल्कि भविष्य को प्रेरणा देने का काम भी करते हैं। भारत और दुनिया के अन्य देशों की धरोहरें हमें विकास और संतुलन का संदेश देती हैं। 'भविष्य की प्रेरणा है, अतीत की धरोहरें'–यह केवल एक भावनात्मक कथन नहीं है बल्कि मानव सभ्यताओं का गहरा सत्य है। जब हम यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थलों को देखते हैं तो समझ में आता है ये पत्थरों, स्मारकों, खंडहरों से कहीं अधिक हैं। क्योंकि वे गुजरे अतीत के जीवित दस्तावेज हैं।

इटली के प्राचीन नगर हों या भारत की विविध सांस्कृतिक विरासतें हों, ये सब हमें सिखाती हैं कि समाज कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं और टूटकर फिर नये सिरे से कैसे उभरते हैं? दरअसल, विश्व धरोहरें अपने भीतर संघर्ष, सृजन, कला और ज्ञान की परतें समेट होती हैं। आज जब दुनिया तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, तब ये धरोहरें हमें जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती हैं। जो सभ्यताएं अपनी धरोहरों को समझती और सहेजती हैं, दरअसल वही टिकाऊ और संतुलित विकास की राह पर आगे बढ़ पाती हैं। वास्तव में विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानव सभ्यताओं की असली पूंजी क्या है, आर्थिक ताकत या सांस्कृतिक विरासत? हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व धरोहर दिवस केवल स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों का उत्सवभर नहीं है बल्कि यह उस सांस्कृतिक स्मृति का सम्मान है, जो मानव सभ्यता को पहचान देती है। अगर इस नजरिये से हम दुनिया पर नजर डालें तो बेहद दिलचस्प तस्वीर नजर आती है। क्योंकि भले आज अमेरिका और रूस जैसी ताकतें दुनिया की प्रमुख ताकतें हों, लेकिन जब विश्व धरोहर स्थलों की कसौटी के आधार पर दुनिया के अलग-अलग देशों को उनके अतीत की हैसियत को आंकते हैं, तो अमेरिका दुनिया की पहली 10 महान विरासतों वाली शक्तियों में अपनी जगह नहीं बना पाती। दुनिया में कुल 1100 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिन्हें यूनेस्को ने पूरी दुनिया के लिए अद्वितीय और मानव विरासत करार दिया है। इसमें सांस्कृतिक यानी कल्चरल विरासतें भी हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक विरासतें भी हैं और मिक्स्ड यानी मिश्रित विरासतें भी हैं। विश्व धरोहर स्थलों के आधार पर हम दुनिया के 10 देशों की गिनती करें तो पहले नंबर पर इटली है, जहां 59 से ज्यादा वैश्विक धरोहरें हैं, जिनमें रोमन साम्राज्य और पुनर्जागरण की विरासतें प्रमुख हैं। भारत दुनिया के 10 प्रमुख वैश्विक धरोहरों वाले देशों के नक्शे में 6वें नंबर पर आता है। आज के समय में अमेरिका भले दुनिया की सबसे शक्तिशाली महाशक्ति हो, लेकिन इतिहास के नजरिये से न केवल अमेरिका बल्कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे सम्पन्न देश किसी गिनती में आते। विश्व धरोहर स्थलों का तमगा उन्हीं देशों को मिला है, जहां सदियों से सभ्यताएं फलती-फूलती रही हैं। रोम का साम्राज्य, वेनिस की जल सभ्यता, चीन की महान दीवार, फॉरबिडेन सिटी जैसी सभ्यता और सांस्कृतिक मूलक विरासतें समूची पृथ्वी की चेतना और सौंदर्यबोध का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश जो आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से आज दुनिया के शक्तिशाली देश हैं, उनके पास अतीत की महान विरासतें नहीं हैं, हैं भी तो बहुत कम मात्रा में। लेकिन शहरीकरण और तकनीकी प्रगति को देखें तो ये आधुनिक किस्म की धरोहरों को रच रही हैं। इसलिए ये देश भले पुरानी धरोहरों के मामले में कम नजर आते हों, लेकिन भविष्य को दिशा देने के मामले में अपनी बेजोड़ जगह बनाते हैं। दरअसल, विश्व धरोहरों की अवधारणा यूनेस्को द्वारा इस बात की समझ से तय हुई है कि अतीत में जो कुछ मनुष्य की गरिमा बढ़ाने वाला रहा है, वह भले किसी भी देश का महान धरोहर हो, लेकिन वह समूची दुनिया की मानवता का प्रतिनिधित्व करता है।

मनुष्यता का शोकगीत बनती महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा

जब स्कूल निशाना बनते हैं तो ज्ञान मरता है। जब अस्पताल मलबे में बदलते हैं तो करुणा दम तोड़ती है, और जब तेल-गैस संयंत्र जलते हैं तो जीवन का ईंधन समाप्त होता है। सच तो यह है कि यह केवल युद्ध की नहीं, मानवता की पराजय है। धरती पर इंसानियत फिर लहूलुहान है। दुनिया बारूद की गंध में सांस ले रही है, बारूद के धुएं में बच्चों की हंसी, स्कूलों की घंटियां और अस्पतालों की शांति सब कुछ घुल गया है। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के युद्ध ने सभ्यता के मुंह पर एक बड़ा काला धब्बा छोड़ दिया है।

युद्ध के दौरान जिस तरह बमबारी हुई है उससे मची तबाही और राष्ट्राध्यक्षों के सनकभरे बयानों ने संवेदना की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। अब युद्ध केवल सीमाओं का नहीं रहा, वह विचारों, अर्थव्यवस्था और नैतिक मूल्यों पर भी आक्रमण कर चुका है। ईरान, अमेरिका, इस्राइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस-यूक्रेन, हर मोर्चे पर निर्दोषों का लहू बहा है और महाशक्तियां हथियारों के व्यापार में लिप्त हैं। यदि सभ्यता का अंत युद्ध की धूल और बारूदी धुएं में ही होना है, तो फिर विकास का अर्थ क्या रह जाएगा?अमेरिका की एक मिसाइल ने ईरान के एक शहर में ऐसी तबाही मचायी कि लोगों की रूह कांप उठी, मानवता कराह उठी। दक्षिणी ईरान के मीनाब में एक नौसैनिक अड्डे के पास स्थित शजारेह तैय्येब प्राथमिक विद्यालय पर हुए मिसाइल हमले में 7-12 साल उम्र की 165 मासूम बच्चियां मारी गईं। इन छोटी बच्चियों के शव किसी भी नीति-निर्माता, किसी भी बयान या किसी भी धर्म के पक्ष में दिए गए तर्कों को झुठला रहे हैं। उधर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध ने अमानवीयता का एक और अध्याय जोड़ दिया है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान की सरहद पर भी अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर बम बरसे हैं। पाकिस्तानी सेना ने पिछले महीने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ओमिद नशा मुक्ति

अस्पताल पर हवाई हमला कर अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। हमले में करीब 400 लोगों की मौत हो गयी और सैकड़ों लोग घायल हुए। इसके अलावा भी रिहायशी इलाकों और स्कूलों पर हमले हुए हैं। इन घटनाओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर यह युद्ध किसके लिए है और किसके खिलाफ है? यह सिर्फ बच्चियों और मरीजों की मौत का आंकड़ा नहीं है अपितु मनुष्यता का शोकगीत है। ये घटनाएं इस सदी की सबसे बड़ी शर्म हैं जो मानवता और नैतिकता के माथे पर गाढ़ा धब्बा बनकर दर्ज हो चुकी हैं। हास्यास्पद बात ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इन हमलों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो शुरू में एक बचकाना बयान देते हुए यहां तक कह दिया था कि स्कूल पर 'ईरान ने खुद बम गिराया' है। लेकिन बाद में राजनीतिक बचाव करते हुए कहा गया कि निशाना साधने में चूक हुयी है। उधर पाकिस्तान का अस्पताल पर हमले से इनकार भी उतना ही झूठा और खोखला है, जितना सूरज की रोशनी में अंधकार की बात करना। सवाल यह नहीं है कि बटन किसने दबाया, सवाल यह है कि मरे कौन। उत्तर स्पष्ट है-बच्चे, बीमार, और निर्दोष नागरिक। राष्ट्राध्यक्षों की ज़िद, तानाशाही प्रवृत्ति और शक्ति की होड़ ने यह सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक युग में युद्ध अब सीमा की नहीं, बल्कि स्वार्थ, सनक और अहंकार की राजनीति है।ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई तथा अनेक सैन्य कमांडरों के अमेरिका व इस्राइल के हमलों में मारे जाने के बाद ईरान बदले की आग में धधक रहा है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही अमेरिकी सैन्य बेस वाले खाड़ी के मुस्लिम देशों पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किये हैं। इन हमलों में भी बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। इन देशों में नागरिकों की हर सुबह मौत के खौफ और रातें 'कल क्या होगा' की बेचैनी में कटी हैं।

कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं रही। बमों की दिशा बदल सकती है, पर दर्द का पता हर बार वही रहता है, आम आदमी के सिर तक। ईरान के हमलों ने यह जता दिया कि प्रतिशोध अब भूगोल नहीं देखता। आज की दुनिया का सबसे भयावह दृश्य यह है कि युद्ध बढ़ रहे हैं, और समानांतर रूप से हथियार-व्यापार फल-फूल रहा है। इन युद्धों के बीच अमेरिका अनेक देशों को 'सुरक्षा' के नाम पर हथियारों की डील दे रहा है। यानी युद्ध जितना फैलता है, मुनाफ़ा उतना बढ़ता है।

चंपतनेवादा में दो पक्ष भिड़े, पथराव में अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त

पुराना विवाद फिर भड़का, गांव में बढ़ा तनाव, पूरी रात पुलिस बल तैनात, हालात पर नजर

➪ इंस्पेक्टर जितेन्द्र राजपूत की तत्परता से टला बड़ा बवाल, शुक्रवार को एसडीएम,एसीपी पहुंचे

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। ककवन थाना क्षेत्र के चंपतनेवादा गांव में गुरवार की रात दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। गाली-गलौज से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते पथराव तक पहुंच गया। इस दौरान उछले ईंट-पत्थरों में से एक पास में स्थापित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर जा लगा, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही ककवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई, जिसके बाद एसडीएम और एसीपी समेत आसपास के थानों का फोर्स भी गांव पहुंचा और हालात को काबू में किया। दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए देर तक हंगामा करते रहे। एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद से विवाद सुलग रहा था। गुरवार रात प्रतिमा स्थल के पास फिर से कहासुनी हुई और मामला मारपीट व पथराव में बदल गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पथराव के दौरान प्रतिमा को आंशिक नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर

घटना के बाद गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

तहरीर मिलते ही देर रात दर्ज हुआ केस

चंपतनेवादा निवासी राकेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने देर रात नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि 16 अप्रैल की शाम गांव के कुछ लोग जयराम के घर के सामने लगी डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचा रहे थे। विरोध करने पर शिवम पुत्र शिवचरन के साथ मारपीट की गई और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की गई। साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस ने अजीत यादव, सोनू यादव, कुलदीप यादव, दीपक यादव और अतर सिंह को नामजद करते हुए कुछ अज्ञात महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसीपी मंजय सिंह ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस फोर्स की मौजूदगी में लगी नई प्रतिमा, बसपा कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण

घटना के बाद क्षतिग्रस्त हुई डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। हालांकि माहौल को शांत रखने के लिए गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से पहल करते हुए शुक्रवार सुबह पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नई प्रतिमा लगवा दी। नई प्रतिमा स्थापित होने के बाद बसपा कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सामाजिक एकता और शांति बनाए रखने का संदेश दिया। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से नई प्रतिमा स्थापित होने से स्थिति सामान्य करने में मदद मिली। ग्रामीणों ने प्रशासन के साथ मिलकर शांति बनाए रखने का संकल्प भी लिया। पुलिस प्रशासन ने नई प्रतिमा स्थापित होने के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही है। वहीं एसडीएम मनीष कुमार और नायब तहसीलदार चंद्र प्रकाश राजपूत ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।

बाथरूम में झांकने का विरोध पड़ा भारी, भाइयों पर तलवार से हमला

➪ विरोध करने पर आरोपी पक्ष ने दी जान से मारने की धमकी
➪ बीच-बचाव में पहुंचे भाइयों पर धारदार हथियार से हमला

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर/कानपुर नगर। अरौल थाना क्षेत्र के गूजेपुर गांव में युवती के साथ अभद्रता का विरोध करना परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि पड़ोसी युवक द्वारा बाथरूम में झांकने की घटना का विरोध करने पर उसके परिजनों ने युवती के भाइयों पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

पीड़िता मौना पुत्री श्रीराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 12 अप्रैल को वह अपने घर के बाथरूम में नहा रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला छोटू पुत्र सुरेंद्र घर की बाउंड्री से झांक रहा था। विरोध करने पर वह भाग गया। बाद में शिकायत करने जब वह आरोपी के घर पहुंची तो वहां मौजूद अंकित पुत्र मुन्नू ने उल्टा उसे ही डांटते हुए गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।

बताया गया कि उसी रात करीब 9:30 बजे जब पीड़िता के भाई मिथलेश और विकास खेत से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अंकित ने तलवार से हमला कर दिया। हमले में विकास की उंगली कटकर अलग हो गई, जबकि गर्दन और हाथ में गंभीर चोटें आईं। वहीं मिथलेश

के पैर और हाथ पर भी तलवार से वार किया गया, जिससे वह लहूलुहान हो गए। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें भी धमकाया और मिथलेश की पीठ पर वार कर फरार हो गया। घायल भाइयों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें हैलट रेफर कर दिया।

पीड़िता ने 14 अप्रैल को थाने पहुंचकर घटना की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने छोटू और अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।अरौल इंस्पेक्टर जनार्दन यादव ने बताया कि कविता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

नेवादा टोल प्लाजा पर बवाल, रोडवेज परिचालक ने लगाया मारपीट व लूट का आरोप

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कानपुर-अलीगढ़ हाईवे स्थित नेवादा टोल प्लाजा पर गुरवार सुबह उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब एक रोडवेज बस के परिचालक और टोल कर्मियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परिचालक ने टोल कर्मचारियों पर मारपीट करने और नकदी लूटने का गंभीर आरोप लगा दिया।

➪ टोल कर्मियों संग विवाद के बाद हंगामा, पुलिस बोली प्रथम दृष्या आपसी कहासुनी

जानकारी के अनुसार कन्नौज की ओर से कानपुर जा रही रोडवेज बस जैसे ही नेवादा टोल प्लाजा पर पहुंची, उसी दौरान परिचालक और टोल कर्मियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। परिचालक का आरोप है कि टोल कर्मियों ने उसे पीटकर घायल कर दिया और उसके पास मौजूद करीब 25 हजार रुपये छीन लिए। घटना के दौरान टोल प्लाजा पर मौजूद अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया और लोग मौके पर जुटने लगे।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। वहीं पुलिस पूरे मामले को प्रथम दृष्टया आपसी विवाद मानकर जांच में जुटी है। इंस्पेक्टर शिवराजपुर अमित सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत करा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रेकी के बाद पूर्व टोल मैनेजर पर हुआ था हमला

नेवादा टोल प्लाजा पहले भी विवादों को लेकर चर्चा में रहा है। आए दिन टोल कर्मियों और वाहन चालकों के बीच कहासुनी व मारपीट की घटनाएं सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां व्यवस्थाओं की कमी और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनती है, जिससे टोल प्लाजा लगातार सुर्खियों में बना रहता है। हाल ही में एक और गंभीर मामला सामने आया था, जब एक टोल कर्मी पर रेकी कराने का आरोप लगा। इसके बाद पूर्व टोल मैनेजर राहुल भदौरिया पर टोल पहुंचकर आधा दर्जन युवकों ने हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टोल कर्मी समेत कई आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस घटना के बाद भी टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए थे।

अफसरों की मेहरबानी से दम तोड़ रही योजना

लाखों खर्च के बाद भी खंडहर बना सामुदायिक शौचालय

ओडीएफ के दावे फेल, पानी-सफाई बिना बेकार पड़ा शौचालय, ग्रामीण फिर खुले में जाने को मजबूर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने के लिए बनाए गए सामुदायिक शौचालय जमीनी स्तर पर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। रसूलाबाद विकास खंड के मिर्जापुर लकोटिया गांव में लाखों रुपये की लागत से बना सामुदायिक शौचालय आज बदहाली का शिकार होकर खंडहर में तब्दील हो चुका है।

शौचालय की स्थिति इतनी खराब है कि वहां जाने वाले लोगों को पानी तक नसीब नहीं होता। न कोई कनेक्शन, न टंकी से सप्लाई। अंदर सीटें टूटी हुई हैं, गेट क्षतिग्रस्त है और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। हालत यह है कि लोग मजबूर होकर फिर से खुले में शौच जाने लगे हैं, जिससे ओडीएफ अभियान के दावे पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं।

हैरानी की बात यह है कि शौचालय पर कहीं भी ÷सामुदायिक शौचालय÷ तक नहीं लिखा गया है।

न ही किसी केयरटेकर का नाम या जिम्मेदारी अंकित की गई है। निर्माण के बाद सिर्फ व्हाइट सीमेंट से पुताई कर खानापूर्ति कर दी गई और बाद में इसे पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिया गया।

ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में जमकर अनियमितताएं हुई हैं। लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद गुणवत्ता शून्य रही। कुछ ही समय में शौचालय जर्जर हो गया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात देखने की जरूरत नहीं समझी।सबसे गंभीर सवाल अफसरों की भूमिका को लेकर खड़े हो रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और सचिव की लापरवाही के साथ-साथ ब्लॉक मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक के अफसरों की मेहरबानी से यह पूरी योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। खंड विकास अधिकारी से लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआर ओ) तक निगरानी की जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल दिखाई दे रहे हैं।

सरकारी निर्देशों के अनुसार सामुदायिक शौचालयों में पानी, सफाई और केयरटेकर की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसके लिए नियमित बजट भी जारी होता है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह व्यवस्थाएं कहीं नजर नहीं आतीं। कागजों में शौचालय चालू दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में वह महीनों से बंद पड़ा है।ग्रामीणों का कहना है कि केयरटेकर के नाम पर धनराशि भी निकाली जा रही है, लेकिन मौके पर कोई कर्मचारी तैनात नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है

और जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। रसूलाबाद विकास खंड के अन्य गांवों में भी इसी तरह के हालात सामने आ रहे हैं, जहां सामुदायिक शौचालय सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। कहीं ताले लटके हैं, कहीं पानी नहीं है तो कहीं भवन जर्जर हो चुका है।

इस पूरे मामले ने स्वच्छ भारत मिशन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक ओर सरकार स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर अफसरों की लापरवाही और मनमानी के चलते योजनाएं धरातल पर फेल हो रही हैं। इस सम्बन्ध में जिले के डीपीआरओ विकास पटेल से कई बार सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया है।

हाइटेंशन लाइन गिरने से पांच मवेशियों की मौत

» लापरवाही को लेकर प्रशासन पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के कपासी गांव में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब गांव के बीचों-बीच गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाइटेंशन लाइन अचानक टूटकर नीचे गिर गई। कुछ ही पलों में करंट ने कहर बरपाया और छह मवेशी इसकी चपेट में आ गए। इनमें से पांच की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। मृत मवेशियों में चार गाय और एक भैंस शामिल हैं, जो कपासी गांव निवासी किसान राजेश, महेश और महावीर के थे। सभी मवेशी घर के पास बंधे हुए थे।

ग्रामीणों के अनुसार, सुबह के समय बिजली के तारों पर गिलहरी गुजरने से तेज चिंगारी उठी और देखते ही देखते तार टूटकर जमीन पर आ गिरा। इसके बाद वहां खड़े मवेशी करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पीड़ितों का कहना है कि इस घटना में उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। घटना के बाद गांव में मातम और गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गांव के अंदर से गुजर रही हाइटेंशन लाइन को हटाने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज किया। घटना की सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

ग्राम रोजगार सेवकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान

मानदेय और भुगतान न मिलने से आक्रोश, नौ माह से नहीं मिला मानदेय

ब्लॉक निघासन परिसर में नारेबाजी करते हुए ग्राम रोजगार सेवक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। विकासखंड निघासन क्षेत्र के ग्राम रोजगार सेवकों ने लंबित मानदेय और मनरेगा मजदूरी के भुगतान में लगातार हो रही देरी के विरोध में बीडीओ जयेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रोजगार सेवकों का कहना है कि वे पिछले लगभग 20 वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो सका है।ब्लॉक अध्यक्ष अमर प्रकाश शुक्ला ने बताया कि करीब 10 महीने से उनका मानदेय लंबित है, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण करना बेहद कठिन हो गया है। रोजगार सेवक सुरजीत कश्यप ने बताया कि गांवों में मनरेगा के तहत काम कर चुके मजदूरों की मजदूरी भी पिछले करीब 5 महीनों से नहीं मिली है, जिससे ग्रामीणों में भी भारी नाराजगी है।

रोजगार सेवकों के अनुसार भुगतान न होने के कारण ग्राम पंचायतों में मनरेगा से जुड़े विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक मानदेय और मजदूरी का समय से भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे।इस दौरान ग्राम रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अमर प्रकाश शुक्ला के नेतृत्व में आशीष कनौजिया, संजय गुप्ता, तिलकराम, इमरान खान, सुरजीत सिंह, आनंद कुमार, दुर्गेश कुमार मिश्रा, राजेश कुमार मौर्या, अनिल कुमार, मोहन यादव, पिंटू वर्मा, श्रीराम सहित बड़ी संख्या में रोजगार सेवक मौजूद रहे।

बच्चों के प्रोजेक्ट्स देख कर अधिकारियों ने दी शाबाशी

पीएम श्री विद्यालय बाढ़ापुर में नवाचार की धूम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। पीएम श्री विद्यालय बाढ़ापुर में आयोजित प्रोजेक्ट बेस लर्निंग मेला इस बार केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि बच्चों की प्रतिभा, वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता का जीवंत प्रदर्शन बनकर उभरा। गांव के इस विद्यालय में सजे मेले ने यह साबित कर दिया कि संसाधनों की कमी के बावजूद यहां के बच्चे हुनर में किसी से पीछे नहीं हैं।

मेले में छात्र-छात्राओं ने विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक मुद्दों और तकनीक से जुड़े दर्जनों वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किए। जल संरक्षण, सोलर ऊर्जा, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और डिजिटल शिक्षा जैसे विषयों पर बनाए गए मॉडल न सिर्फ आकर्षक थे, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली ने मौजूद अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट्स की व्याख्या की, जिसने सभी को प्रभावित किया।

कार्यक्रम में डायट उप प्राचार्य पंकज यादव, डायट मेंटर विपिन कुमार शांत, खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार तथा एसआरजी अनंत त्रिवेदी ने मेले का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने एक-एक मॉडल का बारीकी से अवलोकन किया और बच्चों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन शिक्षा को किताबों से निकालकर व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हैं, जो नई शिक्षा नीति की मूल भावना है।

इस अवसर पर प्रथम संस्था से संदीप यादव, सभासद अमृता कुशवाहा तथा एसएमसी अध्यक्ष प्रवेंद्र श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए विद्यालय की पहल को सराहनीय बताया। मेले को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षकों कंचन यादव, सुमन यादव, सुरेखा यादव, दिव्या सक्सेना, उमा देवी और दिनेश चंद्र पाठक की अहम भूमिका रही। उनके मार्गदर्शन में बच्चों ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, कोटेदारों, अभिभावकों और बड़ी संख्या में ग्रामीणो की उपस्थित रहे।

मेले ने दिया बड़ा संदेश

बाढ़ापुर का यह आयोजन बता गया कि यदि सही दिशा और मंच मिले, तो गांव के बच्चे भी नवाचार और विज्ञान की दुनिया में नई पहचान बना सकते हैं। यह मेला केवल प्रदर्शनी नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा की बदलती तस्वीर का मजबूत संकेत बनकर उभरा।

तपती धूप और लू से दोपहर में सन्नाटा, शाम को बढ़ी रौनक

» ठंडे पेय पदार्थों, पानी, शरबत और जूस की मांग में तेजी आई

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद, कानपुर देहात। क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी और झुलसाती लू ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह से ही सूरज के तेवर तीखे हो जाते हैं और दोपहर तक तापमान अपने चरम पर पहुंच जाता है। ऐसे में लोग बेवजह घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और अपने जरूरी कार्य सुबह या फिर शाम के समय ही निपटा रहे हैं।

गर्मी का असर लोगों की दिनचर्या पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तेज धूप और लू के थपेड़ों के चलते दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा छा जाता है। सड़कों पर आवाजाही कम हो जाती है और लोग घरों में ही रहना सुरक्षित समझते हैं। वहीं, सुबह और खासकर शाम ढलते ही बाजारों में चहल-पहल बढ़ जाती है और खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। भीषण गर्मी के कारण लोगों को प्यास भी अधिक लग रही है, जिससे ठंडे पेय पदार्थों, पानी, शरबत और जूस की मांग में तेजी आई है। दुकानदारों के अनुसार इन दिनों ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री में खासा इजाफा हुआ है।हालांकि रात के समय तापमान में हल्की गिरावट से लोगों को कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन दिन की तपिश अब भी लोगों को बेहाल किए हुए है। लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों की जीवनशैली में बड़ा बदलाव ला दिया है और हर कोई इससे बचने के लिए एहतियात बरतने में जुटा हुआ है।

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो
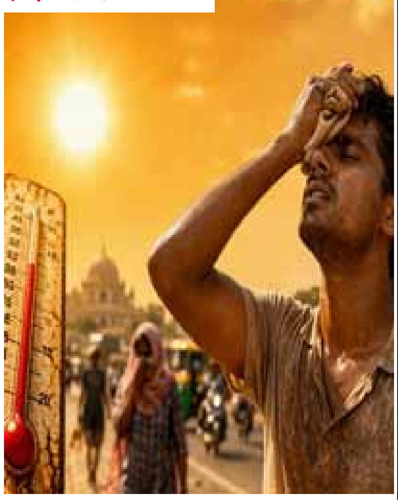

नाबालिग को बहला कर ले जाने में चार पर दर्ज हुआ मुकदमा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला कर भगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि वह अपने पति के साथ खेत पर गेहूं की कटाई करने गई थी।

इसी दौरान उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। आरोप है कि इसी मौके का फायदा उठाकर कदौरा थाना क्षेत्र के मवई गांव निवासी सुल्तान उसे अपने साथ ले गया। पीड़िता का आरोप है कि इस पूरी वारदात में सुल्तान के साथ सुनील, रोहित और नैंसी भी शामिल थे। सभी ने मिलकर पहले से साजिश रची और घटना को अंजाम दिया। पुलिस सर्विलांस टीम की मदद से मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी तलाश कर रही है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामला बेहद संवेदनशील है और हर पहलू से गहन जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम लगाई गई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

किताबों के बहाने 'कमाई का खेल'!
निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक बेहाल

चिह्नित दुकानों से खरीदारी का दबाव, महंगी किताबें थमाकर बढ़ाया जा रहा आर्थिक बोझ

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले निजी स्कूल एक बार फिर अपनी मनमानी को लेकर कटघरे में हैं। नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत होते ही भोगनीपुर क्षेत्र में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर चिह्नित दुकानों से ही किताबें, कॉपियां और स्टेशनरी खरीदने का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया है। यह सिर्फ एक स्थानीय शिकायत नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जड़ें जमा चुके उस 'सिस्टम' की झलक है, जहां पढ़ाई से ज्यादा कमाई प्राथमिकता बनती जा रही है।

अभिभावकों का आरोप है कि एडमिशन के समय स्कूल प्रबंधन बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और रियायतों का सपना दिखाते हैं, लेकिन सत्र शुरू होते ही महंगी किताबों और सामग्री की लंबी सूची थमा दी जाती है। इतना ही नहीं, साफ निर्देश दिया जाता है कि यह सामग्री केवल तय दुकानों से ही खरीदी जाए। इससे अभिभावकों की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और वे मजबूरी में अधिक कीमत चुकाने को बाध्य होते हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, जिन दुकानों का नाम स्कूल बताते हैं, वहां वही किताबें बाजार से कहीं ज्यादा कीमत पर बेची जा रही हैं। इससे यह संदेह गहराता जा रहा है कि स्कूल और दुकानदारों के बीच सांठगांठ का खेल चल रहा है। शिक्षा के नाम पर यह एक तरह का संगठित आर्थिक शोषण बनता जा रहा है, जहां बच्चों के भविष्य का हवाला देकर अभिभावकों की जेब पर सीधा वार किया जा रहा है।मामले को और गंभीर बनाता है यह तथ्य कि कई स्कूल सरकारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए एनसीईआरटी की किताबों के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लागू कर रहे हैं। जबकि उद्देश्य सस्ती और मानकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराना है, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। शिकायतें बढ़ने पर अभिभावकों ने मामला एमएलसी प्रतिनिधि अनुराग दिवाकर तक पहुंचाया। पुखरायां, राजपुर और शाहजहांपुर क्षेत्र के तीन निजी स्कूलों पर विशेष आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में इसे ÷सेटिंग-गेटिंग का पूरा नेटवर्क बताया गया है, जिसमें स्कूल और दुकानदार दोनों की मिलीभगत की आशंका जताई गई है।

नियम क्या कहते हैं?

- एनसीईआरटी/राज्य बोर्ड की किताबें प्राथमिकता- सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूलों को सस्ती और मानकीकृत शिक्षा के लिए एनसीईआरटी या निर्धारित पाठ्यक्रम की किताबें ही लागू करनी चाहिए।
- एक दुकान से खरीदारी का दबाव गैरकानूनी- किसी भी स्कूल द्वारा अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करना नियमों के खिलाफ है।
- मूल्य पारदर्शिता जरूरी:- स्कूलों को किताबों और अन्य सामग्री की सूची सार्वजनिक करनी होती है, ताकि अभिभावक कहीं से भी खरीद सकें।
- शिकायत पर कार्रवाई का प्रावधान:-बेसिक शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को ऐसी शिकायतों पर जांच कर दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है।
- दंडात्मक कार्रवाई संभव:- नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है या आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

बीएसए को पत्र देते एमएलसी प्रतिनिधि अनुराग दिवाकर

मामले की गंभीरता को देखते हुए एमएलसी प्रतिनिधि ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। वहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्र ने कहा है कि शिकायत की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अभिभावकों का कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन कार्रवाई केवल आश्वासन तक सीमित रह जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार प्रशासन वास्तव में सख्ती दिखाएगा या फिर यह मामला भी कागजों में दबकर रह जाएगा।

88 क्वार्टर देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को 88 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे के निर्देश पर जनपद में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को चौकी पुलिस मुगल रोड पर गश्त कर रही थी। तभी एक युवक को रुकने का इशारा किया, वह घबराकर भाल रोड की ओर भागने लगा। संदेह गहराने पर चौकी इंचार्ज गुरेन्दर सिंह ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर दबोच लिया। युवक ने अपना नाम बुढ़ना गांव निवासी वीर सिंह बताया। युवक के थैले से देशी शराब के 88 क्वार्टर बरामद हुए। थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह शराब कहां से लाया था और किसे सप्लाई करने जा रहा था।

घरों में घुसकर चोरी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। थाना मूसानगर पुलिस ने घरों में घुसकर चोरी करने वाले दो शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का एक मोबाइल फोन और 23,300 नकद बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, 27 मार्च को ग्राम गुढ़ा निवासी संजय सिंह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद

15 अप्रैल को ग्राम खिरियनपुरवा निवासी रामकुमार ने भी चोरी की घटना को लेकर मुकदमा कराया। दोनों घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस टीम लगातार सक्रिय थी। इसी क्रम में गुरुवार को चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने मुर्तजानगर मोड़ स्थित पिंटू के ढाबे के पास से कल्लू अहमद निवासी ग्राम अतिबलपुर मूसानगर व मोहम्मद जुम्मन निवासी ग्राम निबियाखेड़ा सजेती को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर अभियुक्तों के पास से कीपैड मोबाइल, 34100 नकद बरामद हुए। पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि वे अपने साथी आवेश निवासी ग्राम जुनैदापुर मूसानगर और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा है। कल्लू अहमद के खिलाफ पूर्व में चोरी, गैंगस्टर एक्ट और शस्त्र अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मोहम्मद जुम्मन पर भी चोरी, लूट, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। वहीं फरार अभियुक्त आवेश और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

छुट्टियों में 'गायब' अफसरों पर शिकंजा, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना पड़ेगा भारी

» लगातार शिकायतें मिल रही कि कुछ अधिकारी बिना सूचना मुख्यालय छोड़ देते

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद में छुट्टियों के दौरान मुख्यालय से गायब रहने वाले अधिकारियों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) विधान जायसवाल ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक अवकाश के दिनों में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ना अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीडीओ द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि शासन स्तर पर पहले से ही यह व्यवस्था लागू है कि किसी भी अधिकारी को अवकाश के दौरान मुख्यालय छोड़ने से पहले सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है।

इसके बावजूद लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ अधिकारी नियमों को दरकिनार कर छुट्टियों में बिना सूचना मुख्यालय छोड़ देते हैं, जिससे जनहित से जुड़े कार्य प्रभावित होते हैं और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

प्रशासन ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अब इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा है। सीडीओ ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि भविष्य में कोई भी अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ता पाया गया, तो उसके खिलाफ उत्तरदायित्व तय कर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी कपिल सिंह कानपुर देहात को भी प्रेषित कर दी गई है, ताकि इसकी सख्ती से निगरानी हो सके और आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन की इस सख्ती के बाद यह माना जा रहा है कि अब छुट्टियों के नाम पर 'गायब' रहने वाले अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगेगी और सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी।

सतहरिया सीएचसी में इलाज नही सिर्फ रेफर का ठिकाना बना अस्पताल

विधानसभा में गूंजी ट्रामा सेंटर की मांग भी बेअसर, जर्जर व्यवस्था पर टिकी मरीजों की उम्मीदें

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर ब्लॉक के औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए बना यह अस्पताल महज मलहम-पट्टी और रेफर सेंटर बनकर रह गया है। गंभीर मरीजों को इलाज के बजाय यहां से सीधे जिला अस्पताल या दूसरे शहरों के लिए भेज दिया जाता है, जिससे कई बार रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं।

अस्पताल में आधुनिक जांच उपकरणों की भारी कमी है। एक एक्स-रे मशीन, जो किसी फैक्ट्री द्वारा गिफ्ट में दी गई थी, रखरखाव के अभाव में खराब पड़ी है और केवल शोपीस बनकर रह गई है। मजबूरी में मरीजों को निजी अस्पतालों और जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है, जहां उन्हें आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है।

औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां दुर्घटनाएं आम बात हैं। सतहरिया चार जनपदों प्रयागराज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ के बीच स्थित है और जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आपात स्थिति में समय पर इलाज मिल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यहां ट्रामा सेंटर होता तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं।

ट्रामा सेंटर की मांग लंबे समय से उठती रही है। तत्कालीन विधायक डॉ. सुषमा पटेल ने विधानसभा में 50 बेड के ट्रामा सेंटर का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब तक यह मांग कागजों में ही सीमित है। उद्यमियों और सामाजिक संगठनों ने भी कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है।

सीएचसी की बदहाली का आलम यह है कि अस्पताल के गेट पर लगा जर्जर बोर्ड भी अपनी स्थिति खुद बयान करता नजर आता है। कई बार निरीक्षण के लिए आने वाले जिम्मेदार अधिकारी भी औपचारिकता निभाकर लौट जाते हैं, जिससे व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता की नाराजगी को देखते हुए यह मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा जनमुद्दा बन सकता है, जो चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए चुनौती साबित होगा

स्थानीय उद्यमी सुनील यादव का कहना है कि गंभीर मरीजों को 50 से 110 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाता। वहीं समाजसेवी विनय सिंह का मानना है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। इस संबंध में अतिरिक्त सीएचसी अधीक्षक डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि ट्रामा सेंटर के लिए प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सुनील यादव

विनय कुमार सिंह

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बाइक-ऑटो-ट्रैक्टर बैन

- » दुर्घटनाओं पर लगाम के लिए एनएचएआई का बड़ा फैसला
- »बागपत समेत कई इलाकों के लोगों के लिए तगड़ा झटका

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा फैसला लेते हुए बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर जैसे धीमी गति के वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस निर्णय से खासतौर पर बागपत क्षेत्र के लोगों को बड़ा झटका लगा है।एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, यह कॉरिडोर आधुनिक और हाई-स्पीड यातायात के लिए विकसित किया गया है। ऐसे में धीमी गति के वाहनों के चलने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। पिछले वर्ष और चालू वर्ष के हादसों के विश्लेषण में सामने आया कि अधिकतर दुर्घटनाओं में दोपहिया और ऑटो सवार ही प्रभावित हुए, जिनमें कई लोगों की मौत भी हुई। अब इस रोक को बढ़ाते हुए मवीकलां से देहरादून तक पूरे कॉरिडोर पर लागू कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने के साथ-साथ वाहनों को सीज भी किया जाएगा।कॉरिडोर पर तेज रफ्तार वाहनों के लिए भी स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है। कारों के लिए अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रकों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। तय सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाने पर ऑटोमैटिक चालान कटेगा।एनएसएआई के मुताबिक हाईवे पर निगरानी के लिए अत्याधुनिक एएनपीआर कैमरे, रडार बेस्ड व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम और इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं।ये कैमरे सीट बेल्ट न पहनने, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने जैसे नियम उल्लंघन को भी रिकॉर्ड कर स्वतः चालान जारी करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

उद्घाटन से पहले ही उजागर हुआ 'घोटाला'?

निघासन उपमंडी की सड़क उखड़ी 4 करोड़ का निर्माण सवालों में

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार की गई निघासन उपमंडी का हाल उद्घाटन से पहले ही उसकी गुणवत्ता की पोल खोल रहा है। करीब 4 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से बनी इस उपमंडी में निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालत यह है कि परिसर के अंदर डामर (तारकोल) से बनी सड़क कई स्थानों पर उखड़ चुकी है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सीधा संदेह गहराने लगा है।

मानकों की अनदेखी का आरोप, ग्रामीणों में रोष, जांच और कार्रवाई की मांग तेज

निघासन और लुधौरी ग्राम समाज की करीब 1.546 हेक्टेयर भूमि पर विकसित इस उपमंडी को क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी सुविधा के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसकी सड़क बदहाल हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, कई हिस्सों में सड़क से डामर पूरी तरह गायब हो चुका है और नीचे की गिट्टी बाहर निकल आई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया गया।

ग्रामीणों का कहना है कि जब करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क की यह स्थिति है, तो बाकी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठना लाजिमी है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित विभाग ने मिलकर घटिया सामग्री का उपयोग किया, जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई है।

हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। न ही मरम्मत या जांच की दिशा में कोई सक्रिय पहल दिख रही है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर रोक लग सके और भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोहराई न जाए।

वाह रे सिस्टमः एम्बुलेंस की लापरवाही ने ली किसान की जान

» जिला अस्पताल से रेफर के बाद मुरादाबाद ले जाते समय बिगड़े हालात, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में निजी एंबुलेंस चालक की कथित लापरवाही के चलते एक घायल किसान की बीच रास्ते दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मुरादाबाद ले जाते समय पहले एंबुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गया और कुछ ही दूरी पर पेट्रोल भी खत्म हो गया, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल सका और किसान ने दम तोड़ दिया।पटवाई थाना क्षेत्र के अहमदनगर गांव निवासी कुलदीप सिंह बुधवार देर शाम बाइक से धमोरा जा रहे थे।पुरैना गांव के पास अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर मुरादाबाद रेफर कर दिया गया।आरोप है कि जिला अस्पताल के बाहर से बुक की गई निजी एंबुलेंस में आवश्यक इंतजाम नहीं थे। रास्ते में ऑक्सीजन सपोर्ट खत्म हो गया और कुछ दूरी बाद एंबुलेंस का पेट्रोल भी समाप्त हो गया, जिससे वाहन बीच सड़क पर रुक गया। अस्पताल तक समय पर न पहुंच पाने के कारण घायल किसान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।घटना से आक्रोशित परिजनों ने हाईवे पर हंगामा करते हुए एंबुलेंस में तोड़फोड़ कर दी। हालात बिगड़ते देख चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह परिजनों को शांत कराया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी कुलदीप राणा के मुताबिक मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपा सिंह ने भी निजी एंबुलेंस की लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।

सड़क बनी संग्राम का मैदान

इंटरलॉकिंग विवाद में लाठी रॉड से हमला, चार लहूलुहान

पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमले का आरोप, एक की हालत नाजुक, लखनऊ रेफर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। तहसील क्षेत्र के उछहपाली पूरे रघुनंदन गांव में सड़क निर्माण का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि पूर्व प्रधान जय नारायण उर्फ काला तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चार लोगों पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।घटना में रामकृपाल, सुरेन्द्रनाथ, विनोद और प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल की हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिस पर प्रशासन की चुप्पी ने आग में घी का काम किया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले को कमजोर करने की कोशिश की है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक सड़क के लिए शुरू हुआ विवाद अब खून तक पहुंच गया। सवाल यही है, जिम्मेदार कौन?

अस्पताल या अखाड़ा? स्टाफ नर्स के व्यवहार से मरीज हुए बेहाल!

सरकारी इलाज छोड़ निजी अस्पताल का 'रास्ता' दिखाने के आरोप, विवादों में घिरी नर्स पर फिर सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी के श्री राम चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, यहां तैनात स्टाफ नर्स अनामिका यादव के व्यवहार को लेकर मरीजों और तीमारदारों में भारी नाराजगी है। आरोप है कि वह समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंचतीं, जिससे इलाज के लिए आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।

इतना ही नहीं, मरीजों से अभद्र व्यवहार और सरकारी इलाज के बजाय निजी अस्पताल जाने की सलाह देने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि नर्स अनामिका का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले भी कई बार उनके खिलाफ शिकायतें सामने आ चुकी हैं, यहां तक कि शांति भंग की कार्रवाई भी हो चुकी है। अस्पताल का अन्य स्टाफ भी उनके व्यवहार से असहज बताया जा रहा है। सवाल यह है कि जब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के दावे कर रही है, तो ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि मरीजों को सम्मानजनक और बेहतर इलाज मिल सके।

ठाठ — अयोध्या मंडी परिषद बना 'गेमिंग ज़ोन'!

कुर्सी पर पैर, मोबाइल में लेवल अप,जनता लाइन में डाउन

» टैक्स के पैसों पर 'आराम लीग' खेलते कर्मचारी, वायरल वीडियो ने खोली पोल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या मंडी परिषद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रशासनिक कक्ष का नजारा किसी सरकारी दफ्तर से ज्यादा गेमिंग लाउंज जैसा दिख रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि स्वराज इंडिया नहीं करता है। कर्मचारी साहब कुर्सी पर पैर रखकर पूरे आराम से मोबाइल गेम खेलने में व्यस्त हैं, मानो फाइलें नहीं, बल्कि लेवल क्लियर करना ही उनकी ड्यूटी हो। जनता का काम?

वो शायद अगली अपडेट में होगा। जिस दफ्तर में किसानों और व्यापारियों की समस्याएं सुनी जानी चाहिए, वहां कर्मचारी स्क्रीन टाइम बढ़ाने में लगे हैं। और सबसे खास बात इस आराम के लिए उन्हें बाकायदा सरकारी वेतन भी मिल रहा है।वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठना लाजिमी है क्या मंडी परिषद में काम खत्म हो गया है, या जिम्मेदारी? गर यही हाल है, तो उस मंडी की व्यवस्था कैसी होगी, जहां का प्रशासन खुद पॉज मोड में है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। फिलहाल वीडियो वायरल है, लेकिन कार्रवाई अभी भी लोडिंग में नजर आ रही है।

सीजफायर का दावा, लेकिन भरोसा अधूरा

इजरायल-लेबनान तनाव पर 10 दिन की 'मोहलत'

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन के अस्थायी सीजफायर का दावा कर पश्चिम एशिया की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता विफल रही और क्षेत्र में तनाव चरम पर बना हुआ है। ट्रंप के मुताबिक, यह समझौता लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अमेरिकी मध्यस्थता से संभव हुआ।

वॉशिंगटन डीसी में हुई इस अहम बैठक को 34 वर्षों में दोनों पक्षों के बीच सबसे महत्वपूर्ण संवाद माना जा रहा है। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद रहे। समझौते के तहत 240

- वॉशिंगटन बैठक के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान
- हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण पर अटका भविष्य
- ईरान डील में पाकिस्तान की एंट्री से कूटनीति तेज

घंटों के लिए संघर्षविराम लागू रहेगा, जिसका मकसद सैन्य टकराव को अस्थायी विराम देना है। हालांकि इस सीजफायर की सफलता पूरी तरह लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह के रुख पर निर्भर मानी जा रही है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण हो। फिलहाल संगठन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे इस पहल की विश्वसनीयता पर

सवाल उठ रहे हैं।

विशेषज्ञ इसे 'कूलिंग ऑफ पीरियड' मान रहे हैं, जिसमें दोनों पक्ष अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर इस दौरान हिंसा नहीं बढ़ती, तो आगे स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत का रास्ता खुल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को ईरान और अमेरिका के संबंधों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने किसी भी वार्ता से पहले इजरायल-लेबनान संघर्ष को रोकने की शर्त रखी थी। ऐसे में यह सीजफायर भविष्य की कूटनीतिक प्रक्रिया की अहम कड़ी बन सकता है।

इसी बीच ट्रंप ने ईरान डील को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद में कोई समझौता होता है, तो वह खुद वहां जाकर हस्ताक्षर में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की भूमिका की सराहना करते हुए पाकिस्तान को 'रचनात्मक मध्यस्थ' बताया। फिलहाल जमीनी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सीमावर्ती इलाकों में लोग राहत की उम्मीद से घर लौटने लगे हैं, लेकिन आशंका बनी हुई है कि अगर रॉकेट हमले जारी रहे, तो इजरायल की जवाबी कार्रवाई इस सीजफायर को तोड़ सकती है। कुल मिलाकर, यह 10 दिन का

- 10 दिन (240 घंटे) का अस्थायी सीजफायर लागू
- वॉशिंगटन में 34 साल बाद बड़ी बैठक
- हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण पर टिकी शांति
- ईरान वार्ता से जुड़ा पूरा घटनाक्रम
- पाकिस्तान की मध्यस्थता से कूटनीति में नई हलचल
- ट्रंप ने इस्लामाबाद जाने के संकेत दिए

संघर्षविराम पश्चिम एशिया में शांति की एक छोटी खिड़की जरूर खोलता है, लेकिन इसकी सफलता कई अनिश्चित कारकों पर निर्भर है। आने वाले दिनों में ही तय होगा कि यह पहल स्थायी समाधान की ओर बढ़ेगी या फिर एक और असफल कूटनीतिक कोशिश बनकर रह जाएगी।

प्लास्टिक उद्योग के दिग्गज

बजरंग लाल तापड़िया फोर्ब्स सूची में शामिल

स्वराज इंडिया ब्यूरो

नई दिल्ली/मुंबई। भारत के 'प्लास्टिक किंग' के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति बजरंग लाल तापड़िया ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। 91 वर्षीय तापड़िया ने Forbes द्वारा जारी 'इंडियाज 100 रिचेस्ट' सूची में 99वां स्थान हासिल किया है। उनकी कुल संपत्ति करीब 3.22 अरब डॉलर (लगभग 28 हजार करोड़ रुपये) आंकी गई है।

तापड़िया ने वर्ष 1942 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान Supreme Industries की स्थापना एक छोटे से उद्यम के रूप में की थी। आज यह कंपनी देश की अग्रणी प्लास्टिक उत्पाद निर्माता कंपनियों में शामिल है। कंपनी औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए विविध उत्पाद तैयार करती है और पूरे भारत में इसके 35 से अधिक कारखाने संचालित हैं।

सुप्रीम इंडस्ट्रीज का कारोबार अब वैश्विक स्तर पर भी फैल चुका है। कंपनी के उत्पाद 55 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं, जिससे भारत की औद्योगिक छवि को मजबूती मिल रही है।

इसके अलावा, तापड़िया की Supreme Petrochem में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, जो निर्माण और पैकेजिंग उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले पॉलीस्टाइनिन का उत्पादन करती है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि बजरंग लाल तापड़िया की सफलता भारतीय उद्यमिता, दूरदृष्टि और निरंतर मेहनत का प्रतीक है, जो नई पीढ़ी के उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

डिजिटल दुनियां में एलआईसी के कदम

लॉन्च किए दो नए डिजिटल ऐप

स्वराज इंडिया ब्यूरो

मुंबई। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने डिजिटल सेवाओं को मजबूत करते हुए दो नए मोबाइल ऐप MyLIC (ग्राहकों के लिए) और Super Sales Saathi (एजेंटों के लिए)—लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स के जरिए कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर, तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा एजेंटों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है।

मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एम. नागराजु की उपस्थिति में इन ऐप्स का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एलआईसी के शीर्ष प्रबंधन ने इसे कंपनी के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम बताया।

- भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्राहकों और एजेंटों को दी बड़ी राहत

LIC के अधिकारियों के अनुसार, ये दोनों ऐप्स कंपनी के DIVE (Digital Innovation & Value Enhancement) प्लेटफॉर्म के तहत विकसित किए गए हैं। इनका उद्देश्य ग्राहकों, एजेंटों और कर्मचारियों को एकीकृत, सुरक्षित और सहज डिजिटल अनुभव प्रदान करना है।

इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि LIC अब केवल पारंपरिक बीमा कंपनी नहीं, बल्कि डिजिटल सेवाओं के माध्यम से एक आधुनिक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में उभर रही है।

इन ऐप्स के लॉन्च से अब ग्राहकों को शाखाओं के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और ज्यादातर काम मोबाइल से ही हो सकेंगे। वहीं एजेंटों को भी ग्राहकों तक बेहतर तरीके से पहुंचने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ग्राहकों के लिए MyLIC ऐप की खासियतें

- MyLIC ऐप के जरिए पॉलिसीधारकों को कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी–
- सभी बीमा पॉलिसियों का एक जगह प्रबंधन
- प्रीमियम का आसान और त्वरित भुगतान
- पॉलिसी लाभों की रियल-टाइम ट्रैकिंग
- ऑनलाइन पॉलिसी अपडेट और रिन्यूअल
- पेपरलेस सेवाएं और सुरक्षित ई-केवाईसी
- नई पॉलिसी खरीदने और तुलना की सुविधा

एजेंटों के लिए Super Sales Saathi

- Super Sales Saathi ऐप को खासतौर पर एजेंटों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है
- डिजिटल बिक्री उपकरण और ग्राहक प्रबंधन
- रियल-टाइम पॉलिसी स्टेटस ट्रैकिंग
- फॉलो-अप के लिए ऑटोमैटिक रिमाइंडर ग्राहकों से बेहतर संवाद की सुविधा
- AI आधारित सुझाव (nudges) से बिक्री में सुधार
- प्रदर्शन और लक्ष्य की निगरानी के लिए डैशबोर्ड

LIC का यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश में डिजिटल सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। MyLIC और Super Sales Saathi ऐप्स के जरिए कंपनी ने न केवल ग्राहक सुविधा बढ़ाने बल्कि बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को भी नया आयाम देने की कोशिश की है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com